राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
32वीं बैठक - दिनांक : 20 मार्च, 2010 का कार्य वृत्त

उत्तराखंड में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 तक की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 32वीं बैठक होटल मधुबन, देहरादून में दिनांक 20 मार्च, 2010 को आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तराखंड डा. रमेश पोखरियाल " निःशंक " तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के करकमलों से दीप प्रज्जवलित कर सम्पन्न किया गया।

इस बैठक में विशिष्ट अतिथि श्री एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सचिव, श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त), श्री अनूप वधावन, प्रमुख सचिव (शहरी विकास) उत्तराखंड शासन, श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल, श्री डी. मुजमदार, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल, श्री वी. एस.बाजवा , महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं श्री पी. दास, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक का संबोधन -

माननीय मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों के अभिनन्दन के पश्चात श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल ने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों द्वारा राज्य के विकास में योगदान एवं राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के सहयोग हेतु आभार प्रकट किया। उन्होंने इस क्रम में चलाई जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं में बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2009 तक की गई प्रगति से सदन को अवगत कराया।

उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सदन में उपस्थित प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ऋण-जमा अनुपात ही प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड है, और प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाने एवं ऋण ग्रहण क्षमता (Credit Absorption Capacity) सृजित करने की आवश्यकता है। प्रदेश के ऋण प्रवाह में गति लाने के उद्देश्य से इसके लिए कौन-कौन से क्रेडिट इनपुट्स (Credit Inputs) चाहिए , उसका पता लगाया जा सकता है ताकि गरीब जनता के साथ-साथ राज्य के समग्र उत्थान में बैंक सार्थक सहयोग प्रदान कर सके।

उत्तराखंड के नेसर्गिक पर्यावरण में सौगात के रुप में प्राप्त जड़ी-बूटी का यथोचित दोहन करके उत्पादक क्षेत्र को बिना क्षति पहुँचाए, हम पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व को आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध करा सकते हैं। **'' मुख्यमंत्री जड़ी-बूटी विकास योजना ''** के अंतर्गत राज्य में जड़ी-बूटी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग को नाबार्ड एवं विशेषज्ञों के परामर्श से विभिन्न प्रजातियों के कृषिकरण हेतु क्षेत्र विशेष एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बैंकयोग्य प्रोजेक्ट (Bankable Project) तैयार करने चाहिए। इसके साथ-साथ जड़ी-बूटी उत्पादों के विपणन हेतु संगठित बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में छोटी-छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित कर, उद्यान. बागवानी, बेमौसमी एवं जैविक सब्जियों की खेती का वाणिज्यीकरण किया जा सकता है।

उन्होंने उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्रामों के सार्वगीण विकास हेतु भारतीय स्टेट बैंक ने **''एस.बी.आई. का अपना गाँव ''** के नाम से कुछ गाँवों को अंगीकृत किया है तथा इन गाँवों की भौगोलिक एवं आर्थिक सम्भाव्यताओं के अनुरुप सभी प्रकार के क्रियाकलापों हेतु ऋण उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में सभी जिलों के **'' अटल आदर्श ग्रामों ''** में आवश्यकतानुसार बैंक शाखा या बिजनेस फेसिलिटेटर / बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होने समस्त बैंकों से आग्रह किया कि उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले उन आवंटित अटल आदर्श ग्रामों में जहाँ बैंक शाखा का खोलना सम्भव न हो, वहाँ पर इन्टरनेट आधारित मोबाइल बैंकिंग या अन्य वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होने सदन को अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैक के निर्देशानुसार **2000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त गाँवों में मार्च, 2011** तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त बैकों द्वारा अपनी-अपनी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

अंत में उन्होंने बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन -

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत एवं शुभकामनाएं प्रदान करते हुए पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि राज्य के हरिद्वार एव उधम सिंह नगर जिले का ऋण-जमा अनुपात हटा दिया जाए तो राज्य का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम रह जाएगा। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के जिलों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि लाने हेतु उद्यान,. ग्राम्य विकास, कृषि विभाग, नाबार्ड तथा अग्रणी जिला प्रबंधक आपस में चर्चा कर अपने-अपने क्षेत्र की संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक के आधार पर ग्राम्य एवं कृषि विकास की योजनाएं बनाकर चरणबद्ध एवं समयबद्ध रणनीति तैयार कर जिले में लागू करें।

उन्होने सदन में उपस्थित शासन के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से पिछली तिमाही से अब तक के तुलनात्मक प्रगति जाननी चाही, जिस पर सर्वप्राथम सचिव (उद्यान) ने बताया कि उनके विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित रु. 3.5 करोड़ लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है। दिनांक 09 नवम्बर, 2009 को आरम्भ की गई **'' मुख्यमंत्री संरक्षित खेती योजना ''** और **'' मुख्यमंत्री जड़ी-बूटी योजना ''** के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन आरम्भ कर दिया गया है। राज्य में 7 से 10 ग्रामों के एग्रो क्लाइमैटिक जोन आधारित 320 क्लस्टर चिन्हित किए जा चुके हैं जिसमें वृक्ष, झाड़ी एवं घास प्रजाति की जड़ी-बूटी का कृषिकरण किए जाने की योजना है और इसके लिए 30 स्थानों पर नर्सरी स्थापित की गई हैं। प्रत्येक जिले में एक **'' मॉडल गार्डन ''** बनाने का लक्ष्य है जिसमें इच्छुक कृषकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्लान्टिंग मेटिरियल (Planting Materials) भी तैयार किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सचिव (उद्यान) को निर्देशित किया कि बैंकों द्वारा समस्त (26) चिन्हित जड़ी-बूटियों हेतु ऋण वितरण के लिए '' स्केल ऑफ फाइनेंस '' निर्धारित करवाने की व्यवस्था करें।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य की निर्धारित वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष बैंकों द्वारा उपलब्धि बहुत कम रही है और वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, इसलिए कृषि, उद्योग, उद्यान एवं पर्यटन विभाग बैंकों के साथ बैठकर शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों में लम्बित आवेदनों को निस्तारित कराएं। इस संदर्भ में सदन में उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से वितरित किए कई ऋणों पर देय अनुदान राशि अब तक लम्बित है, जिसके कारण लाभार्थियों पर ब्याज का बोझ अधिक पड़ रहा है और बैंकों में अलाभकारी आस्तियाँ (Non Performing Assets) भी बढ़ रही है। इसकी प्रतिक्रिया में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पर्यटन विभाग को आगाह करते हुए कड़े निर्देश दिए कि वे 10 दिनों के अंदर संबंधित अनुदान धनराशि लाभार्थियों के खातों में समायोजित करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि जिनके द्वारा बैंक से वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं में अनुदान राशि लम्बित है, को भी दिनांक 31 मार्च, 2010 तक समायोजित करना सुनिश्चित करें, जैसे कि के.वी.आई.सी. / के.वी.आई.बी., पी.एम.ई.जी.पी., उत्तराखंड सार्वभौम रोजगार योजना, नवीन ऋण सह-अनुदान आवास योजना आदि।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने **'' अटल आदर्श ग्राम योजना ''** को सफल बनाने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वह इन ग्रामों में मार्च, 2011 तक बैकिंग सुविधायें, बैंक शाखा अथवा बिजनेस कोरसपोंडेंट / बिजनेस फेसिलिटेटर के माध्यम से उपलब्ध करवाएं। इन ग्रामों में राज्य सरकार पहले से ही समस्त मूलभूत अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है, जिसके लिए राज्य में नोडल अधिकारी, श्री गुसांई को नियुक्त किया गया है। इन सभी गाँवों को एक आदर्श गाँव के रुप में विकसित करना है जिसके लिए राज्य सरकार एवं सभी बैंकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता

है। इस दिशा में भारतीय स्टेट बैंक ने ''एस.बी.आई. का अपना गाँव '' के नाम से कुछ गाँवों को अंगीकृत किया है तथा इन गाँवों की भौगोलिक एवं आर्थिक सम्भाव्यताओं के अनुरुप सभी प्रकार के क्रियाकलापों हेतु ऋण उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम चाहते हैं कि इन गाँवों एवं हमारे राज्य के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक भी एक आदर्श बैंक के रुप में उभरे।

उत्तराखंड में उद्यान. बागवानी, बेमौसमी एवं जैविक सब्जियों की खेती की अपार संभावना है। पूरे विश्व में जैविक उत्पाद की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है इसलिए जैविक खेती करने हेतु बढ़ावा देने के साथ-साथ उचित विपणन व्यवस्था एवं प्रचार-प्रसार करना होगा। कृषि एवं बागवानी उपज का प्रसंस्करण कर विभिन्न प्रकार के प्ररिष्कृत / डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ निर्मित किए जा सकते हैं जिसके लिए स्थानीय स्तर पर छोटी-छोटी प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करनी होंगी।

राज्य के विकास में उत्तराखंड की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका एवं भागीदारी है, परंतु बैंकों द्वारा महिलाओं को वित्तपोषण बहुत कम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिला स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं लेकिन उन सभी का बैंक लिंकेज नही हो पाया है। इस दिशा में प्रशासन एवं बैंकों को सार्थक प्रयास करने की आवश्यता है। महिलाओं में उद्यमिता विकसित करने हेतु उनका कौशल विकास करने की आवश्यकता है जिससे कि उनके द्वारा निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारा जा सके।

राज्य में पंचकर्म, योग एवं आध्यात्म का व्यवसायीकरण करने के लिए भारत एवं विश्व के दूसरे भाग में प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरुप अधिकाधिक संख्या में अतिथि एवं पर्यटक प्रदेश में पधारें एवं अपने तन-मन के शुद्धिकरण हेतु योग एवं आध्यात्म से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा साथ-साथ प्रदेश को अधिक राजस्व की भी प्राप्ति हो सकेगी।

उन्होंने उत्तराखड राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के **प्राकृतिक संसाधनों** एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए साहसिक पर्यटन जैसे - राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्नो-स्कीइंग, मॉउन्टेन बाइकिंग एवं ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों को राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ अतिरिक्त आकर्षण के रुप में सम्मिलित किया जा सकता है।

अंत में उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा की गई अब तक की उपलब्धि संजोषजनक तो है किंतु इसमें और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। अंत में शुभ कामनाएं और धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया।

श्री एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सचिव. उत्तराखंड शासन ने ऋण-जमा अनुपात पर हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में संरक्षित एवं विविध (diversified) खेती की प्रबल संभाव्यता का उपयोग करते हुए प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने बताया कि राज्य में 12,000 वन पंचायतों के अंतर्गत मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए समुचित भूमि उपलब्ध है जिसके उपयोग के लिए कृषि, पशुपालन एवं वन विभागों को कार्य योजना बनाने हेतु निर्देशित किया। उन्होने कहा कि बैंक एवं राज्य सरकार के बीच उचित समन्वय स्थापित करने हेतु सरकारी विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि बैंकों से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके एवं सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनओं में लम्बित अनुदान राशियों को बैंक खातों में यथासमय समायोजित करवाया जा सके। मुख्य सचिव ने बैंकर्स स्थाई समितियों की तीनों बैठकों में राज्य सरकार एवं बैंकों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता न किए जाने पर असंतोष प्रकट करते हुए निर्देशित किया कि भविष्य में इन बैठकों में समस्त संबंधित अधिकारी अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।

उन्होने आगे सभी बैंकों को निर्देशित किया कि रु. 1 करोड़ तक के ऋण **'' क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ''** (**सी.जी.एफ.टी.एस.आई.**) के अंतर्गत बिना संपार्श्विक प्रतिभूति (Without Collateral Security) के सुगमतपूर्वक दिए जाएं । उन्होने बैंकों द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों पर शीघ्र काईवाई करने हेतु राजस्व विभाग को समस्त जिला प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने को कहा।

श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (**एफ.आर.डी.सी.**) ने अपने संबोधन में बैकों से अपेक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्यान उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है ताकि बाजार में समुचित मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि पहाड़ों पर छोटे-छोटे पॉली हाऊस फार्मिंग करने को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग को व्यापक प्रचार-प्रसार करना होगा और जिसके उत्पाद के विपणन हेतु मार्केटिंग चेन बनाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ बैकों को भी इस क्षेत्र में उदारतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी।

बैकों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रश्न, कि ग्रामीणों के लिए भूमि अभिलेख (खसरा-खतौनी) प्राप्त करने की **'' कम्प्यूट्रीकृत ऑन लाइन ''** सुविधा ब्लाक स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होने बताया कि यह सुविधा राजस्व विभाग द्वारा तहसील स्तर पर उपलब्ध है, जिसको ग्रामीणों के लिए संबंधित लेखपाल (पटवारी) सत्यापित कर उपलब्ध करवा सकते हैं।

उन्होने पशु पालन विभाग एवं बैंकों से **'' बिग डेयरी योजना ''** जिसमें 10 दुधारु पशु पालने की व्यवस्था है, को प्रदेश में व्यापक स्तर पर संचालित करने पर बल दिया ताकि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके।

अंत में उन्होने अपने संबोधन में पुनः विचार प्रकट किया कि गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र के कमिशनर को भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक मे आमंत्रित किया जाए ताकि इस बैठक में लिए गए निर्णयों का जनपद स्तर पर कार्यान्वयन किया जा सके।

सभा के अंत में **श्री जे. पी. बहुगुणा, उप महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया** द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक द्वारा सभी बैंक अधिकारियों को आगामी बैठक हेतु मार्च, 2010 तक के सही एवं पूर्ण आँकड़ों के विवरण दिनांक 15 मार्च, 2010 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, को भेजने हेतु कहा गया तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

****